अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011

मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु बुधवार 18 जनवरी, 2012 सायं–4.15

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा का असली चेहरा देश के सामने आया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। ऐसा महसूस होता है कि भाजपा लोकायुक्त बनाने में संजीदा नहीं है। बार–बार कानूनी पेचीदगियां पैदा करना बार–बार कोई न कोई बहाना बनाना, गुजरात सरकार नहीं चाहती कि वहां पर लोकायुक्त बने। भाजपा का यह दोहरा मापदण्ड है। दिल्ली में वो सख्त लोकायुक्त की बात करते हैं। संसद में संघीय ढ़ांचे पर हमले करने को कहते हैं, अगर लोकायुक्त बनाने की बात की जाती है। जन्तर–मन्तर पर लोकायुक्त बनाने की बात करते हैं और गुजरात के अन्दर लोकायुक्त नहीं बनाना चाहते। पिछले आठ साल से लगातार गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। और आज एक बार फिर उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ गुजरात सरकार उच्चतम न्यायालय में जाने की बात कही है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जा सकते हैं उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ लेकिन इससे भाजपा की नीयत का पता चलता है कि वे लोकायुक्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और अगर मैं यह कहूं कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने में संजीदा नहीं हैं, तो यह बात गलत नहीं होगी। वो केवल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जुबानी जमा–खर्च करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते। हमने लोकसभा के अन्दर लोकपाल के कानून को पास किया, राज्यसभा में उन्होंने पास नहीं होने दिया क्योंकि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं। संसद में वे कुछ और जुबान बोलते हैं, जन्तर–मन्तर पर कोई और जुबान बोलते हैं, मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं और गुजरात के अन्दर किसी और तरीके से अमल करते हैं। यही भाजपा का असली चेहरा है।

ऊपर कही गई बातों के मद्देनजर एक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नरेन्द्र मोदी के सामने बौनी साबित हो रही है, श्री राशिद अलवी ने

कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहता, चूंकि यह उनका अन्दरूनी मामला है कि कौन ज्यादा कद का नेता है और कौन कम कद का नेता है।

आडवाणी जी ज्यादा बड़े हैं। या नरेंद्र मोदी जी अधिक बड़े हैं। यह फैसला भाजपा का है हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

अरूण जेटली द्वारा जारी एक बयान की एनडीए के शासनकाल में राज्यपालों की नियुक्ति वहां के मुख्यमंत्री से सलाह करके की जाती थी, परन्तु अब तो संघीय ढ़ाचे पर हमला हो रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर श्री राशिद अलवी ने कहा कि अगर किसी को भी अथवा भाजपा को यह महसूस होता है कि हम संघीय ढ़ांचे के विरूद्ध है तो हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक ही तमाम प्रान्तों एवं सूबों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगर किसी को लगता है कि हम संविधान के खिलाफ काम करते हैं, और संविधान का कहीं उल्लंघन होता है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं, वो अदालत में जा सकते हैं।

बिहार में साईकिल घोटाला के विषय में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि मुझे इसकी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है लेकिन अगर ऐसा है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

कल पश्चिम बंगाल के मंत्रिमण्डल के एक कांग्रेसी मंत्री द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं को सरकार से निकालने की अनुमति मांगने पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर श्री राशिद अलवी ने कहा कि समाचार–पत्रों के माध्यम से ऐस पता चला है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी इस विषय में किसी नतीजे पर पहुंचेगी, मीडिया को सूचित किया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के मध्य किसी भी प्रकार के टकराव के विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह कहना कि सत्ता के अलावा कौन सी मजबूरी है, यह गलत है, हम कभी सत्ता के पीछे नहीं रहते, सत्ता में रहने के लिए कोई फैसला नहीं करते। यह बात एक बार नहीं कितनी बार साबित हो चुकी है। परमाणु संधि के मामले में वामपंथी नहीं चाहते थे कि परमाणु संधि पास हो, हमने सत्ता की परवाह नहीं की। वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं, हम उन सिद्धांतों के लिए लड़ाई

लड़ते हैं। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं कि सत्ता हमारे लिए महत्व नहीं रखती, सत्ता एक साधन है प्रोग्रोमों को कार्यान्वित करने का। सत्ता का तरीका होता है अपने सिद्धांतों को असली रूप देने का। टीएमसी के साथ हमारा ऐसा कोई मतभेद नहीं है जो कि चर्चा द्वारा हल न किया जा सके। विचारों में मतभेदों को बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है।

इसी सन्दर्भ में दोबारा पूछे जाने पर कि फिर एमरजेंसी क्यों लगाई थी, श्री राशिद अलवी ने कहा कि मैं इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता।

भारत–सरकार द्वारा विमानन में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह केवल प्रस्ताव है और सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी, तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है।

इसी सन्दर्भ में श्री राशिद अलवी ने पुनः कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, देश और जनता के हित में करेगी।

सलमान रूशदी की भारत में आने को लेकर उठे विवाद के विषय में, श्री राशिद अलवी ने कहा कि जहां तक सलमान रूशदी का जयपुर में आने का प्रश्न है, यह वहां की कानून व्यवस्था से संबंधित है और राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। कोई भी निर्णय लेने के लिए इस विषय को चुनावों से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। हमारी यह राय है कि किसी के भी धार्मिक एवं मज़हबी विचारों एवं ज़ज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है और न उनको ठेस पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत करता है। किसी का भारत में आना या ना आना, इस सवाल का निर्णय सरकार करती है और चूंकि यह राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के मुख्यमंत्री शायद भारत सरकार के गृहमंत्री से इस विषय में मिले हैं, और वे अपना फैसला करेंगे।

एक अन्य प्रश्न कि सलमान रूशदी द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्व0 राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने पर भी जयपुर में बिक रही है, श्री राशिद अलवी ने कहा कि मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यह ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई किताब की बिक्री प्रतिबंधित है तो यह कानूनी मामला है। अगर यह तथ्य राजस्थान सरकार की जानकारी में है, तो वहां की सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह कहना कि हाथी चिन्ह को सुरक्षित भी किया जा सकता है, इस पर श्री राशिद अलवी ने कहा कि चुनाव आयोग के किसी भी निर्णय पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो कुछ भी उचित समझेगा वो करेगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। वो किसी भी चिन्ह को सुरक्षित रख सकता है। यह प्रश्न चुनाव आयोग से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी इस देश में निष्पक्ष चुनाव चाहती है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। निष्पक्ष चुनाव करवाना देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है।

सेनाध्यक्ष वी. के. सिंह की जन्म तिथि को लेकर उठे विवाद पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सरकार उच्चतम न्यायालय नहीं गई है। इस पर उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम अपनी फौजी सिपाहियों की बहुत इज्ज़त करते हैं, और उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने को उचित नहीं समझते। उच्चतम न्यायालय में सब अपना–अपना पक्ष रखेंगे और अदालत अपना फैसला करेगी। इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस मामले में यह कहना कि सरकार भाग रही है, ऐसा कहना गलत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भाजपा टिप्पणी करती है और इस पर राजनीति करना चाहती है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

हस्त/–
(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव